



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

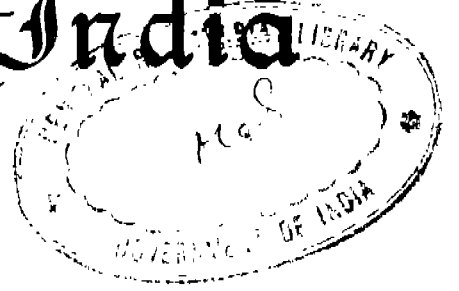
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 309]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2001/कार्तिक 30, 1923

No. 309]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2001/KARTIKA 30, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

विषय :—सिंगापुर, यू एस ए, यूरोपीय संघ तथा चीन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल (आई पी ए) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 46/1/2001-डी जी ए डी.— मैं 0 नशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि०, न घरलू उद्योग की आर स 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिस इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें सिंगापुर, यू एस ए, यूरोपीय संघ तथा चीन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल (आई पी ए) के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. शामिल उत्पाद:

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद सबद्ध देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित आईसोप्रोपाइल एल्कोहल (बल्क तथा पैकड) (जिस इसके पश्चात सबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है और यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 क उपशीर्ष 2905.1201 के अंतर्गत वर्गीकृत है। ये वर्गीकरण केवल सकंतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै0 नेशनल ऑर्गेनिक कॅमिकल इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में आईसोप्रोपाइल एल्कोहल का एक मात्र उत्पादक हैं और इसलिए वह घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदंड का पूरा करता है।

3. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश सिंगापुर, यू एस ए, यूरोपीय संघ तथा चीन हैं (जिस इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है)।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, सबद्ध देशों/क्षेत्र के मूल का या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल का

उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित माल के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

(अ) याचिकाकर्ताओं ने आई सी आई आर - एल ओ आर जो कि यू एस ए, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के लिए समूचे विश्व के रसायनिक उद्योग की एक पूर्णतः स्थापित पत्रिका है, में दर्शाई गई कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। यू एस ए में आईसोप्रोपाइल एल्कोहल की दर्शाई गई कीमत 584 अमरीकी डालर प्रति मी टन, सिंगापुर के लिए 565.50 अमरीकी डालर प्रति मी.टन तथा ई यू के लिए 553.80 अमरीकी डालर प्रति मी० टन है।

प्राधिकारी न यू एस ए, सिंगापुर और यूरोपीय संघ हेतु सामान्य मूल्य के लिए उसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में मान लिया है।

(ब) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन रोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 की परिशिष्ट 1 में दिनांक 15.7.99 की अधिसूचना सं. 44/99-सी यू एस (एन टी) और उसके पश्चात् दिनांक 31 मई, 2001 की अधिसूचना सं. 28/2001 (एन टी) द्वारा सशोधन कर उसमें निम्नलिखित सिद्धांत 7 शामिल किया गया था:-

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत अथवा परिकलित लागत के आधार पर अथवा किसी एस तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा

अथवा जहां यह संभव न हो वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके समान वस्तु हेतु भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबद्ध देश के विकास स्तर और सदर्भाधीन उत्पाद का ध्यान में रखते हुए, उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का विधिवत ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो वहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में यदि जांच की गई हो तो उसकी समय-सीमा का ध्यान भी रखा जाएगा । जांच संबंधी पक्षों का बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपराक्त चयन की सूचना अविलम्ब दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी ।"

इन नियमों में दिनांक 31.5.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 28/2001(एन टी) द्वारा आगे और संशोधन किया गया है जिसके द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत 8 सम्मिलित किया गया है और इसकी टिप्पणी में चीन जनवादी गणराज्य को गर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है ।

इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार गर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका

निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढॉच क बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के लिए उचित मूल्य का पता नहीं चलता है । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या:-

- (i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागत और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, निविष्टि, बिक्रियां एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय बाजारी संकेतों जो आपूर्ति एवं मांग प्रदर्शित करते हैं, क अनुरूप और इस बारे में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप क बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य पर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं,
- (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों क अधीन है जो पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली खासकर परिसम्पत्तियों क मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खातो, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान क कारण आई है,
- (iii) ऐसी फर्में दिवालियापन और सम्पत्ति सबधी ऐस कानूनों क अधीन हैं जा फर्म क प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं, और
- (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है ।

किन्तु रूस और चीन जनवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट कारकों के बारे में लिखित में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं

पाटनरोधी जाच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय (उक्त नियमों के अनुबध्द-1) पैराग्राफ 1 से 6 तक में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है।

टिप्पणी

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चीन जनवादी गणराज्य, जार्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलि, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उज्बेकिस्तान एवं विएतनाम। इनमें से ऐसा कोई देश जो यह प्रमाणित करना चाहता है कि वह इस पैराग्राफ में वर्णित मापदंड के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरा ध्यान दिया जाएगा।

(ग) उपरोक्त यथासंशोधित नियमों के अनुसार याचिकाकर्त्ताओं ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में संबद्ध वस्तुओं के परिकल्पित सामान्य मूल्य के आधार पर किया है।

उपरोक्त नियमों के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक अपने निर्यातों का बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से होने का दावा करते हैं तो उसके लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकारी ने चीन में सामान्य मूल्य के लिए उसे प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में मान लिया है

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अप्रैल, 2000 से जून, 2001 की अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता के जरिए आयात आंकड़े उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ता ने कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़े, बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन तथा बंदरगाह पर खर्चों के लिए समायोजन का दावा किया है।

7. पाटन मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों/क्षेत्र का सामान्य मूल्य उस निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिस पर इसका भारत को निर्यात किया गया है जिससे इस बात का प्रथम दृष्ट्या संकत मिलता है कि निर्यातको द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे बिक्री प्राप्ति में गिरावट, बढ़े हुए स्टॉक, लाभप्रदता में गिरावट समय तथा सचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफो को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करत हैं ।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2001 तक की है ।

11. सूचना देना

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातको और भारत के आयातको को अलग से लिखा जा रहा है कि व निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करे तथा अपने विचारों से अवगत कराएं :-

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

12. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. वी. सप्तगुप्ति, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2001

Subject :—Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Isopropyl Alcohol (IPA) from Singapore, USA, European Union and China.

No. 46/1/2001-DGAD.— M/s National Organic Chemical Industries Limited on behalf of the domestic industry has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) alleging dumping of Isopropyl Alcohol from Singapore, USA, European Union and China and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties.

35894/2001-2

1. **Product involved:** The product involved in the present petition is Isopropyl Alcohol (Bulk & Packed) (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from the subject countries and classified under Customs Sub-heading 2905.1201 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification, is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. **Domestic Industry Standing:** The petition has been filed by the M/s National Organic Chemical Industries Limited, Mumbai. The petitioner is the sole producer of Isopropyl Alcohol in India and, therefore, the petitioner satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry.

3. **Country(ies) involved:** The countries involved in present investigation is Singapore, USA, European Union and China (hereinafter referred to as to as subject countries /territory.)

4. **Like Articles:** The petitioner has claimed that goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries/ territory. Accordingly, Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries/ territory within the meaning of the Rules.

5. **Normal Value:**

(a) The petitioner has claimed normal value based on the price indicating in the ICIR – LOR, a well recognised magazine in the chemical industry world over for USA, South East Asia and North West Europe. The price indicated of Isopropyl Alcohol in USA is US\$ 584 PMT, for Singapore US\$ 565.50 PMT and for EU US\$ 553.80 PMT.

The Authority has considered the same as prima facie evidence for Normal Value for USA, Singapore and EU.

(b) Annexure 1 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 had been amended vide Notification No. 44/99-CUS (NT), dated 15-7-99 and subsequently Notification No. 28/2001(N.T.) dated 31st May, 2001whereby the following Principle 7 had been added:-

“In case of imports from non-market economy countries, Normal Value shall be determined on the basis of the price of constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable

manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

Vide Custom Notification No.28/2001(NT) dated 31.5.2001, further Principle 8 as under has also been inserted and in the Note appended thereto Peoples' Republic of China has been included in the list of non-market economy countries:

"The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in the note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the Designated Authority shall consider as to whether,

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in respect to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether cost of major inputs substantially reflect market values;
- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write off, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 (of Annexure 1 of Rules supra) instead of the principles set out in this paragraph.

Note: For the purpose of this paragraph, the list of non-market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakstan, North Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmeistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the Designated Authority."

- (c) In accordance to the Rules as amended above, the petitioners have claimed Normal Value for China PR based on the basis of Constructed Normal Value of the subject goods in India. In terms of the aforesaid Rules it will be incumbent upon the exporters from the China PR, in case they claim their exports to be from market economy country, to provide sufficient evidence to the Designated Authority in accordance with the aforesaid Rules.

The Authority has considered the Constructed Normal Value as prima facie evidence for Normal Value for China PR.

6. **Export Price:** The petitioner has claimed that Import Statistics are available through DGCI&S, Calcutta for the period April, 2000 to June, 2001. The petitioner has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, and commission to arrive at the ex-factory price.

7. **Dumping Margin:** There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject countries/ territory is higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries/territory.

8. **Injury and Causal Link:** Various parameters relating to injury such as suppressed domestic price, increased stock and reduction in profitability etc. prima-facie indicate collectively and cumulatively that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

9. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** The Designated Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

10. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2000 to 30th June, 2001.

11. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:-

Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
Udyog Bhavan, New Delhi- 110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

13. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

